On the basis of data for the year 1989-90, drugs with a turnover of Rs. 400 lakhs or more, having market competition and drugs with a turnover of Rs. 100 lakhs or above but below Rs. 400 lakhs, having no monopoly situation have, therefore, not come under price control.

(b) Against 142 drugs in price control under DPCO'87, presently there are 76 drugs in price control under DPCO'95. However, these 76 drugs include 21 drugs which were having very high turnover but were outside price control earlier. Studies conducted from time to time after coming into force of DPCO, 1995 indicate that increase of medicine price is generally not across the board and abnormal. There is also decrease in prices in some cases.

(c) Reconsideration is dependent upon availability of updated data as provided for in para 22.7.2 (v) of 'Modifications in Drug Policy, 1986

Non-utilisation of funds allocated for Mid-day meals scheme

4040. SHRI PARAG CHAL1HA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the funds allocated to States by the Centre of finance/subsidise scheme of Mid-day meals, which is in the priority sector, remained unused and were surrendered last year;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what are the details of funds allocated to Kendriya Vidyalayas and what is the utilisation percentage; and

(d) what are the reasons for non-utilisation and what are the steps contemplated for 1996-97 to ensure full utilization of allocated funds?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) to (d) The initial allocation under the Mid-day meal Scheme, launched with effect from 15th August, 1995, was Rs. 611.79 crores in 1995-96. However, releases to the Food Corporation of India upto 31.3.19%, which supplies foodgrains to the States/ UTs were Rs. 441.38 crores. The shortfall was due to the reason that the States took time for adopting and operationalising the scheme.

Shifting of research centre of C.l.F.T.

4041. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to shift the Research Centre of C.l.F.T. at Burla (Orissa) to some other place; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) and (b) Yes, Sir. The Burla Research Centre of the Central Institute of Fisheries Technology (C.l.F.T.) was established in 1963 for the development of fish harvesting techniques in Hirakud Reservoir. The Burla Centre has already served the Orissa fisheries for a period of more than 32 years and has achieved its objectives in Orissa. Having completed its mandate and as per the recommendations of the Fourth Quinquennial Review Team (Q.R.T.) of C.l.F.T. for the period 1986-93, the Cente is being shifted to Madhya Pradesh.

कृषि क्षेत्र में निवेश

4042. श्री ओ॰पी॰ कोहली: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि क्षेत्र में निवेश में गिरावट आई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बैंक द्वारा दिये गये कुल ऋणों की राशि में से वर्ष-वार कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा है; और

(ग) कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है और इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी नहीं। कृषि में निवेश की राशि प्रतिवर्ष बढ़ रही है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा निचले स्तर पर वितरित ऋण में कृषि क्षेत्र के अंश संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं है। बहरहाल विगत तीन वर्षों में प्राथमिकता वाले क्षेत्र में निचले स्तर पर किए गए ऋण वितरण में कृषि क्षेत्र के अंश का ब्यौरा इस प्रकार है:—

(करोड़ रुपये)

वर्ष	प्राथमिकता वाले क्षेत्र को निचले स्तर पर वितरित कुल ऋण	कृषि क्षेत्र का अंश	कृषि क्षेत्र के अंश का प्रतिशत
1	2	3	4
1993-94	26049	16494	63
1994-95	25948	21424	82
1995-96	30345*	24849	82

*अनन्तिम

(ग) कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने में सुधार करने के लिए भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा विभिन्न नीतिगत उपाय किए गए है, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(i) समेकित ग्रामीण विकास परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने एवं उसमें सुधार करने के लिए समुचित उपायों की सिफारिश करने के लिए समिति की नियुक्ति;

(ii) कृषि संबंधी पेशगियों के प्रतिभूति मानदण्डों में संशोधन;

(iii) ऋण तथा पुनर्वित्त संबंधी ब्याज दरों को युक्तियुक्त बनाना;

(iv) राज्य सहकारी बैंकों/केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा व्यक्तियों को ऋण देने का दायरा बढ़ाना;

(v) चूककर्त्ता राज्य भूमि विकास बैंकों को पुनर्वित्त सहायता जारी करने के लिए लचीली नीति अपनाना;

(vi) ड्रिप तथा छिड़काव सिंचाई जैसी नई प्रौद्योगिकी पर बल देना;

(vii) खुम्बी, उत्तक संवर्द्धन, पुष्पोत्पादन, सब्जियों की खेती, खाद्य प्रसंस्करण जैसी उच्च प्रौद्योगिकी वाली स्कीमों के लिए संस्थागत ऋण को बढ़ाने के प्रयास करना; एवं

(viii) छोटी सिंचाई तथा ग्रामीण विकास संबंधी आधारभूत ढांचे के विकास के लिए राज्यों को दीर्घावधि ऋण प्रदान करने की दृष्टि से राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि नामक एक विशेष निधि बनाई जा रही है।

नाबार्ड द्वारा बैंकों को सलाह दी गई है कि खास तौर से कृषि, पुष्पोत्पादन एवं उत्तक संवर्द्धन संबंध नवीन एवं उच्च प्रौद्योगिकी वाली परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु विशेष कृषि शाखाएं खोलें।

Rail track condition in South Central Railways

4043. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the division-wise number of "track fractures" detected in the South Central Railways between 1.1.1996 and 31.7.%; and

(b) the steps being taken to improve the quality of track in Andhra Pradesh by the Railways?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ):

a) Division — Rail/Weld failures

Secunderabad	31
Vijayawada	12
Guntakal	17
Hubii	9
Hyderabad	Nil; and

(b) Steps taken are as under:

(i) Frequent ultrasonic testing of rails to detect flaws in rails and timely replacement of defective rails.

(ii) Renewal of rails and sleepers on age cum condition basis as planned works.